



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 14 जनवरी, 2002/24 पौष, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

मण्डी, 8 जनवरी, 2002

संख्या पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-119-23.—एतद्वारा श्रीमती गौरी देबी, प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि० प्र०) का ध्यान हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नतः है:—

- (ण) “यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं। परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरहंता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथा स्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं अब तक उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती”।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है। अर्थात् 8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने से पूर्व दो या दो से अधिक सन्तानें हैं तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् अतिरिक्त सन्तान या सन्तानें उत्पन्न होती हैं तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा।

इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि आपके 8 जून, 2001 के पश्चात् एक अतिरिक्त सन्तान उत्पन्न हुई है जिसके फलस्वरूप आपकी सन्तान की संख्या दो से अधिक हो गई है जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये।

मण्डी, 8 जनवरी, 2002

संख्या पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-109-13.--एतद्वारा श्री कृष्ण कुमार सुपुत्र श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति गोहर, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि० प्र०) का ध्यान हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो निम्न है :—

(ण) "यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं। परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरहता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं अब तक उसकी उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती।"

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है अर्थात् 8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती हैं तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा।

इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि आपके 8 जून, 2001 के पश्चात् एक अतिरिक्त सन्तान उत्पन्न हुई है जिसके फलस्वरूप आपकी सन्तान की संख्या दो से अधिक हो गई है जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाए।

मण्डी, 8 जनवरी, 2002

संख्या पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-114-18.--एतद्वारा श्री गुरदेव सिंह, पंच, ग्राम पंचायत कसारला, विभाग पंचायत, जिला मण्डी (हि० प्र०) का ध्यान हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के

खण्ड (ग) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नता है :—

✱ (ग) “यदि उसके दो से अधिक जीवन सन्तान हैं। परन्तु खण्ड (ग) के अधीन निरहता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जिसके यथा स्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं अथवा तक उसकी उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती”।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ग) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है। अर्थात् 8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तानें हैं तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् अतिरिक्त सन्तान या सन्तानें उत्पन्न होती हैं तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा।

इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि आपके 8 जून, 2001 के पश्चात् एक अतिरिक्त सन्तान उत्पन्न हुई है जिसके फलस्वरूप आपकी सन्तान की संख्या दो से अधिक हो गई है जो पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 (ग) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये।

हस्ताक्षरित/-  
उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

